हाइटेन पी. डेलाल

बनाम

ब्रातिंन्द्रनाथ बनर्जी

11 जुलाई, 2001

[बी. एन. किरपाल, रूमा पाल और बृजेश कुमार, जे. जे.]

विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992-धारा 3 (2)-1.4.1991 और 6.6.1992 के बीच किए गए अपराधों के विचारण के लिए स्थापित विशेष न्यायालय-दिसंबर 1991 से बीच जारी किए गए चेक और मार्च 1992-धन की अपर्याप्तता के लिए चेक का अनादर वैधानिक अवधि के बाद किए गए अपराधों के लिए विशेष न्यायालय का अधिकार क्षेत्र-माना जाता है कि वैधानिक अवधि प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित है न कि अपराधों से-इसलिए, विशेष न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है क्योंकि चेक जारी करना वैधानिक अवधि के भीतर है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-धारा 118,138 और 139-दायित्व का उपधारणा-अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए चेक का अनादर-अपीलार्थी द्वारा भुगतान के लिए दायित्व से इनकार-अभिनिर्धारित, अनुमान को अस्वीकार करने के लिए सबूत का बोझ अभियुक्त पर है-दोषसिद्धि बरकरार

रखी गई क्योंकि अपीलार्थी बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा-साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 3 और 114।

अपीलार्थी ने एक बैंक के पक्ष में चार चेक जारी किए दिसंबर 1991 से मार्च 1992 के बीच की अवधि के दौरान प्रतिभूतियों में लेनदेन की कुल राशि लगभग रु। 78.46 करोड़। धन की अपर्याप्तता के कारण चेक वापस कर दिए गए। बैंक ने नोटिस जारी किए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपीलार्थी। भुगतान करने में विफल रहने पर, अपीलार्थी को विशेष न्यायालय द्वारा अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसे विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित किया गया था और एक साल के लिए कारावास और रुपये का जुर्माना। 1 एक लाख।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत विशेष न्यायालय का अधिकार क्षेत्र 1.4.1991 और 6.6.1992 के बीच किए गए अपराधों तक सीमित था; कि विशेष न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि अपराध 6.6.1992 के बाद हुआ था; और यह कि कुछ इच्छित सुरक्षा लेनदेन के लिए बैंक को जारी किए गए चेक कभी भी मूर्त रूप नहीं ले पाए और इसलिए बैंक को 900 901 वापस करना चाहिए था।अपीलार्थी को चेक

को भुनाने के बजाय क्योंकि कोई दायित्व नहीं था अपीलार्थी द्वारा आरोपमुक्त किया जाना।

बैंक की ओर से शिकायत दर्ज कराने वाले प्रतिवादी ने तर्क दिया कि विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत निर्धारित वैधानिक अवधि प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित है न कि अपराधों से, और यह कि चेक अपीलार्थी द्वारा बैंक को अपनी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए जारी किए गए थे।

न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया

1. विशेष न्यायालय के उद्देश्यों और कारणों का विवरण(प्रतिभूति लेनदेन) अधिनियम, 1992 और अधिनियम की प्रस्तावना से संबंधित अपराधों का परीक्षण यह स्पष्ट करता है कि अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत निर्दिष्ट अवधि से संबंधित उन विशेष लेनदेनों से निपटना था। इस धारा के तहत, वैधानिक अवधि शब्द लेनदेन के बाद होती है। अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उपयोग की जाने वाली भाषा से यह स्पष्ट है कि अवधि प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित है और अपराध की तारीख मायने नहीं रखती है। इन परिस्थितियों में, विशेष न्यायालय की अधिकारिता का दायरा, चाहे वह आपराधिक कार्यवाही में हो या दीवानी कार्यवाही में विवाद, 1.4.1991 के बाद और 6.6.1992 पर या उससे पहले किए गए प्रतिभूतियों में लेनदेन के संबंध में है। लेन-देन,

अर्थात चार चेक जारी करना, वैधानिक अवधि के भीतर होता है और इसलिए विशेष न्यायालय के पास शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था। [904- डी-एफ; 905-बी; 907-डी]

हर्षद शांतिलाल मेहता बनाम। अभिरक्षक और अन्य, [998] 5 एस. सी. सी. 1, पर भरोसा किया।

मीनू मेहता बनाम शार्क डी. मेहता, [1998] 2 एस. सी. सी. 418, विशिष्ट।

2. उपधारणाएं साक्ष्य के नियम हैं और इसके साथ विरोधाभास नहीं हैं निर्दोषता का उपधारणा, क्योंकि बाद वाले का मतलब यह है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए बाध्य है। अभियोजन पक्ष पर दायित्व का निर्वहन कानून या तथ्य के अनुमानों की मदद से किया जा सकता है जब तक कि अभियुक्त अनुमानित तथ्य के अस्तित्व में न होने की उचित संभावना दिखाने वाले साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, बशर्ते कानून की धारणा का आधार बनाने के लिए आवश्यक तथ्य मौजूद हों, न्यायालय के पास वैधानिक निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई विवेकाधिकार नहीं बचा है। हालाँकि, यह उस व्यक्ति को इसका खंडन करने और इसके विपरीत साबित करने से नहीं रोकता है जिसके खिलाफ उपधारणा की जाती है। इसलिए, खंडन को निर्णायक रूप से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन

इस तरह के साक्ष्य को बचाव के समर्थन में अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि अदालत को या तो बचाव का अस्तित्व मानना चाहिए या इसके अस्तित्व को यथोचित रूप से संभावित मानना चाहिए, [2001]तर्कसंगतता का मानक 'विवेकपूर्ण व्यक्ति' का है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 और 139 के तहत उपधारणाओ को अस्वीकार करने का बोझ अपीलार्थी पर था, एक बोझ जिसका वह निर्वहन करने में विफल रहा। इस तरह के किसी भी प्रमाण के अभाव में, अधिनियम की धारा 138 और 139 के तहत उपधारणा प्रबल होनी चाहिए। [909 -डी-जी; 913-जी-एच; 914-बी]

मद्रास राज्य बनाम ए. वैद्यनाथ लायर, आकाशवाणी (1958) एससी 61; कुंदन लाल रल्लाराम बनाम। अभिरक्षक, निकासी संपत्ति, बॉम्बे, ए. आई. आर. (1961) एस. सी. 1316; धनवंतराई बलवंतराई देसाई बनाम। महाराष्ट्र राज्य, आकाशवाणी (1964) एससी 575 (सीबी); वी. डी. झिंगन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आकाशवाणी (1966) एससी 1762; शैलेन्द्रनाथ बोस बनाम। बिहार राज्य, ए. आई. आर. (1968) एस. सी. 1292; राम कृष्ण बेदु राणे बनाम। महाराष्ट्र राज्य, [1973] 1 एस. सी. सी. 366; त्रिलोक चंद जैन बनाम। दिल्ली राज्य, [1975] 4 एस. सी. सी. 761 और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम। संरक्षक, [2000] 6 एस. सी. सी. 427, का उल्लेख किया गया है।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 688/ 1995 से।

बॉम्बे विशेष न्यायालय, के सी. आर. आई. आवेदन संख्या 1/1992 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 30.4.93 से ।

वी. एस. कोतवाल, पी. एस. सुधीर, मनीष पारिख, पी. वेणुगोपाल और के. जे. जॉन अपीलार्थी के लिए।

वी. ए. बोबडे, तुषार ए. कूपर और के. आर. नाम्बियार प्रतिवादी के लिए। न्यायालय का निर्णय न्यायधीश रुमा पल,जे. द्वारा पारित किया गया:-

भूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 (जिसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138। अपीलार्थी को एक वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। 1 एक लाख, तीन महीने की अवधि के लिए और कठोर कारावास से गुजरना होगा। विशेष न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित,अपीलार्थी ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

इस न्यायालय के समक्ष अपील की सुनवाई के दौरान, सीखा गया अपीलार्थी के वकील ने अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2 की भाषा के आधार पर एक प्रारंभिक मुद्दा उठाया। यह तर्क दिया गया था कि विशेष

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र 1.4.1991 और 6.6.1992 पर या उससे पहले किए गए अपराधों तक सीमित था और कथित अपराध 6.6.92, के बाद हुआ था।

रुमा पाल, जे अपीलकर्ता को विशेष न्यायालय ( प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) अधिनियम , 1992 के तहत स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी पाया गया था ( जिसे कहा गया है, अधिनियम")। अपीलकर्ता को एक वर्ष के कठोर कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। 1 लाख जुर्माना, अन्यथा तीन महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायालय के निर्णय एवं आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है।

इस न्यायालय के समक्ष अपील की सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 की भाषा के आधार पर एक प्रारंभिक मुद्दा उठाया। यह तर्क दिया गया कि विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार 1.4.1991 के बीच और 6.6.1992 को या उससे पहले किए गए अपराधों तक सीमित था और कथित अपराध 6.6.92 के बाद हुआ था, विशेष न्यायालय के पास उस पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। पीठ ने अपील पर सुनवाई करते हुए दिनांक 7.9.1999 के अपने आदेश में दर्ज किया:

प्रथम दृष्टया हम पहले सिद्धांतों पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए विवाद से सहमत नहीं हैं, लेकिन अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के एक फैसले को हमारे ध्यान में लाया है मीनू मेहता बनाम शरक डी. मेहता (1998) 2 एससीसी 418 का मामला । उस मामले के तथ्यों पर पूर्वोक्त निर्णय में यह प्रश्न संभवतः विचार के लिए नहीं उठा था, लेकिन अन्यथा पैराग्राफ 12 में उनके आधिपत्य निष्कर्ष पर आ गए हैं:

'इसलिए, प्रतिभूतियों में किसी भी लेनदेन से संबंधित प्रत्येक अपराध जो अधिनियम के दायरे में आता है, यानी यदि ऐसा लेनदेन 1.4.1991 और 6.6.1992 के बीच या उससे पहले हुआ है तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा। ऐसे अपराध का मुकदमा।' उक्त अनुच्छेद के बाद के भाग में ऐसा मानने के बाद आधिपत्य इस निष्कर्ष पर पहुंचा है:

धारा 3 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अपराध, जो अधिनियम की धारा 7 के दायरे में है, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध होना चाहिए और इसमें निम्नलिखित दो विशेषताएं होनी चाहिए:

1. ऐसा अपराध प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित होना चाहिए; और 2 ऐसा अपराध 1.4.1991 के बीच और 6.6.1992 को या उससे पहले किया गया होना चाहिए।

कानून का यह कथन उनके आधिपत्य ने पहले पैराग्राफ में कही गई बातों के विपरीत है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है और हम ऊपर उद्धृत पैराग्राफ 12 के दूसरे भाग में की गई व्याख्या से सहमत नहीं हैं। मामले को देखते हुए, हम यह उचित समझते हैं कि इस अपील को 3-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।"

इसके बाद मामले को इस बेंच के समक्ष रखा गया और सुनवाई की गई।

मीनू मेहता बनाम शावक डी. मेहता मामले में स्पष्ट रूप से विरोधाभासी टिप्पणियों को अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में समाधान की आवश्यकता है।

यह अधिनियम 6.6.92 को प्रख्यापित किया गया था ताकि "प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना की जा सके।"

विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार धारा 7 में निर्दिष्ट किया गया था और अधिनियम की धारा 3(2) में निर्दिष्ट अपराधों तक सीमित था । धारा 3(2) जहां तक प्रासंगिक है, प्रदान करती है:

"..... 1 अप्रैल 1991 के बाद और 6 जून 1992 से पहले प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित कोई भी अपराध..."

प्रश्न यह है - क्या निर्दिष्ट अवधि "अपराध" शब्द या "लेन-देन" शब्द के योग्य है? यदि यह पूर्व है, तो विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार, जैसा कि अपीलकर्ता ने तर्क दिया है, लेनदेन होने पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर किए गए अपराधों तक ही सीमित होगा। हालांकि, प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि यह अवधि 'लेन-देन' शब्द के योग्य है और यह न केवल वैधानिक प्रावधानों की भाषा से स्पष्ट है बल्कि प्राधिकरण द्वारा भी समर्थित है। हमारे विचार में प्रतिवादी का कथन सही है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण अधिनियम विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) संशोधन अधिनियम, 1994 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण देखें की पृष्ठभूमि और फोकस को इस प्रकार बताता है:

> "सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों दोनों में लेनदेन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और कदाचार देखे गए थे, जो कुछ दलालों द्वारा विभिन्न कर्मचारियों की मिलीभगत से किए गए थे।" बैंक और वित्तीय संस्थान।"

अधिनियम की प्रस्तावना यह भी स्पष्ट करती है कि अधिनियम का उद्देश्य प्रतिभूतियों में उन विशेष लेनदेन से निपटना था। धारा 3 की उपधारा (2) में वैधानिक अवधि लेन-देन शब्द के बाद आती है। यदि अवधि को 'अपराध' शब्द के रूप में वर्गीकृत किया जाता तो धारा में लिखा

होता "1 अप्रैल के बाद और 6 जून 1992 को या उससे पहले कोई भी अपराध" इस्तेमाल की गई भाषा से यह स्पष्ट है कि यह अवधि प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित है और अपराध की तारीख महत्वहीन है। अधिनियम की अन्य धाराएँ यह भी दर्शाती हैं कि अधिनियम का उद्देश्य वे विशेष लेनदेन हैं जो एक विशेष अवधि के दौरान किए गए थे। इस प्रकार अधिनियम की धारा 4 कस्टोडियन को कुछ परिस्थितियों में "अप्रैल 1991 के पहले दिन के बाद और 6 जून 1992 को या उससे पहले किसी भी समय किए गए किसी भी अनुबंध या समझौते को रद्द करने की अनुमति देती है"। स्थिति को धारा 9-ए(1)(बी) (1994 में संशोधन के माध्यम से प्रस्तुत) द्वारा और स्पष्ट किया गया है जो विशेष न्यायालय को सभी क्षेत्राधिकार, शक्तियां और अधिकार प्रदान करता है जो संशोधित अधिनियम के शुरू होने से तुरंत पहले प्रयोग किए जा सकते थे। किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी मामले या दावे के संबंध में -

> "1 अप्रैल 1991 के बाद और 6 जून, 1992 को या उससे पहले दर्ज की गई प्रतिभूतियों में लेनदेन से उत्पन्न, जिसमें एक व्यक्ति उप के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है धारा की धारा (2) 3 एक पार्टी, दलाल, मध्यस्थ या किसी अन्य तरीके से शामिल है।"

इन परिस्थितियों में अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि विशेष न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का दायरा, चाहे आपराधिक कार्यवाही में हो या नागरिक विवादों में, 1 अप्रैल 1991 के बाद और 6 जून को या उससे पहले दर्ज किए गए प्रतिभूतियों के लेनदेन के संबंध में है। 1992. कि धारा 3(2) में उल्लिखित अवधि लेनदेन को संदर्भित करती है न कि अपराध को, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे हर्षद शांतिलाल मेहता बनाम कस्टोडियन और अन्य मामले में इस न्यायालय के पक्ष में पाया गया, इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विचार करने के बाद अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कहा गया है, "इसलिए, सिविल और आपराधिक मामलों में विशेष न्यायालय का अधिकार क्षेत्र 1.4.1991 से 6.6.1992 की वैधानिक अवधि के दौरान लेनदेन के संबंध में है; और संलग्न संपत्तियों के संबंध में है।" एक अधिसूचित व्यक्ति। इसलिए, उक्त अधिनियम का संपूर्ण संचालन इस वैधानिक अवधि के दौरान प्रतिभूतियों में लेनदेन के इर्द-गिर्द घूमता है।"

हमारी राय में मिनो मेहता बनाम शावक डी. मेहता (सुप्रा) में निर्णय इसके विपरीत निर्णय नहीं देता है। उस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दिसंबर 1991 में आरोपी के पास शेयर दर्ज कराए गए थे। आरोपी को शेयरों की बिक्री की व्यवस्था करनी थी और शिकायतकर्ता को बिक्री आय का भुगतान करना था। जनवरी, 1992 में आरोपी ने शेयर बेच दिए और बिक्री से प्राप्त आय का दुरुपयोग किया। इस प्रकार प्रतिभूतियों में लेन-देन और साथ ही

गबन का अपराध दोनों धारा 3 उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान हुए थे। न्यायालय के समक्ष एकमात्र मुद्दा यह था कि क्या विशेष न्यायालय के पास अपराधों से निपटने का अधिकार क्षेत्र होगा, भले ही अभियुक्त को संरक्षक द्वारा सूचित नहीं किया गया हो। विद्वान न्यायाधीशों ने मामले का सकारात्मक निर्णय लिया।

> अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हुए, न्यायालय ने कहा:
> "..... अधिनियम की प्रस्तावना और अधिनियम के अधिनियमन के मुख्य उद्देश्य के आलोक में धारा 7 की योजना ऐसा प्रतीत होता है कि प्रासंगिक अवधि के दौरान प्रतिभूतियों में लेन-देन में शामिल अभियुक्तों के संबंध में अभियोजन से संबंधित सभी आपराधिक कार्यवाही विशेष अदालत के समक्ष होंगी, न कि सामान्य अदालतों के समक्ष क्योंकि धारा एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होती है जिसमें कहा गया है कि कुछ भी निहित होने के बावजूद किसी भी अन्य कानून में, केवल विशेष न्यायालयों को ही ऐसे अपराधों की सुनवाई का विशेष क्षेत्राधिकार होगा।"

क्योंकि अपराध और लेन-देन एक-दूसरे से जुड़े हुए थे, विद्वान न्यायाधीशों ने लेन-देन और अपराध के बीच अंतर नहीं किया जब उन्होंने यह कहकर अपने निष्कर्षों को सारांशित किया:

" धारा 3 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अपराध , जो अधिनियम की धारा 7 के दायरे में है, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध होना चाहिए और इसमें निम्नलिखित दो विशेषताएं होनी चाहिए:

1. ऐसा अपराध प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित होना चाहिए; और

2. ऐसा अपराध 1.4.1991 के बीच और 6.6.1992 को या उससे पहले किया गया होना चाहिए।

आइटम 2 में 'अपराध' शब्द का उपयोग एक स्पष्ट त्रुटि थी क्योंकि इसका मतलब न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 15 में स्पष्ट कर दिया है, जिसमें लिखा है: "इस मामले से अलग होने से पहले हम कह सकते हैं कि विद्वान वरिष्ठ वकील अपीलकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के खिलाफ कथित अपराध प्रासंगिक समय के दौरान प्रतिभूतियों में किसी भी लेनदेन से संबंधित नहीं था, बल्कि उक्त लेनदेन से अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त कथित बिक्री प्रतिफल के लिए योग्य था और जिसके लिए धारा 409 अभियोजन के तहत कथित अपराध था । अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है। इस तर्क से सहमत

होना मुश्किल है। शिकायत में की गई बातों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, जिसे स्पष्ट रूप से इस स्तर पर सच माना जाना चाहिए, यह दिखाएगा कि आरोपी पर लेनदेन में शामिल होने का आरोप है प्रतिभूतियों में, अर्थात्, प्रासंगिक अवधि के दौरान शेयरों और उक्त लेन-देन से बिक्री आय प्राप्त करने का आरोप है जिसे उसने शिकायतकर्ता को नहीं सौंपा है या प्रेषित नहीं किया है जो उक्त राशि का हकदार होने का दावा करता है। इस प्रकार कथित अपराध निश्चित रूप से प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित है, जैसा कि कहा गया है कि आरोपी ने संबंधित अवधि के दौरान लेनदेन किया था।"

इसलिए यह स्पष्ट है कि सारांश न्यायालय के वास्तविक दृष्टिकोण को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करता है। वर्तमान मामले में चार चेक जो आपराधिक कार्यवाही का विषय हैं, अपीलकर्ता द्वारा 24.12.1991, 26.12.1991, 17.2.1992, और 27.3.1992 यानी वैधानिक अवधि के भीतर निष्पादित किए गए थे। आंध्रा बैंक में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (संक्षेप में 'बैंक' के रूप में संदर्भित) के पक्ष में 27 करोड़ रुपये, 14.5 करोड़ रुपये, 17 करोड़ रुपये और 19,95 रुपये की राशि के चेक जारी किए गए थे।,75,000/-

क्रमशः। बैंक के अनुसार ये चेक वैधानिक अवधि के दौरान अपीलकर्ता के माध्यम से या उसके कहने पर बैंक द्वारा दर्ज प्रतिभूतियों में लेनदेन से उत्पन्न बैंक को हुए नुकसान के भुगतान के लिए जारी किए गए थे। बैंक के अनुसार 21.5.1992 को सभी चार चेक "व्यवस्था नहीं की गई" टिप्पणी के साथ आंध्रा बैंक द्वारा अस्वीकृत होकर लौटा दिए गए। बैंक ने अपीलकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत 31.5.1992 और 1.6.1992 को नोटिस जारी किया, जिसमें अपीलकर्ता को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर चार चेक के संबंध में भुगतान करने के लिए कहा गया । अपीलार्थी ने भुगतान नहीं किया। जैसा कि आरोप लगाया गया है कि लेन-देन वैधानिक अवधि के भीतर है, विशेष न्यायालय के पास शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था और इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता की प्रारंभिक आपत्ति खारिज कर दी गई है।

मामले के गुण-दोष के आधार पर भी, हमें विशेष न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। 14 जुलाई, 1992 को ब्रतींद्रनाथ बनर्जी (यहाँ प्रतिवादी) द्वारा बैंक की ओर से दायर शिकायत में, यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता बैंक और

अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच सुरक्षा लेनदेन के संबंध में दलाल के रूप में कार्य कर रहा था।. शिकायत के अनुसार अपीलकर्ता ने बैंक को अपनी देनदारियों के निर्वहन के लिए चार चेक जारी किए थे। चार चेक आंध्रा बैंक को प्रस्तुत किए गए लेकिन बाउंस हो गए। अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 247 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर लिखित बयान में कहा गया था कि बैंक के अधिकारी से मौखिक जानकारी के अनुसार बैंक अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ नई योजना और तरीकों पर काम कर रहा था और इसके लिए सहायता का अनुरोध किया गया था । वही, अपीलकर्ता "आवश्यकता पड़ने पर कुछ औपचारिकताओं और समायोजन" के लिए सहमत हुआ। इस व्यवस्था के अनुसार, अपीलकर्ता ने बैंक को कई चेक निष्पादित और भेजे थे, जिनमें चार चेक (एक्सटेंशन बी, सी, डी और ई) शामिल थे, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से अपीलकर्ता द्वारा सुरक्षा की खरीद के कुछ इच्छित लेनदेन से संबंधित थे। अपीलकर्ता के अनुसार इनमें से कोई भी इच्छित लेनदेन वास्तव में पूरा नहीं हुआ और परिणामस्वरूप चेक पर कभी कार्रवाई नहीं की गई या भुनाया नहीं गया। इस बात से इनकार किया

गया कि अपीलकर्ता चार चेक के संबंध में कोई भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। अपीलकर्ता के अनुसार हालांकि लेन-देन नहीं हुआ था और चेक वापस कर दिए जाने चाहिए थे, लेकिन बैंक द्वारा निरीक्षण के कारण चार चेक अपीलकर्ता को वापस नहीं लौटाए गए।

विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमे के विभिन्न प्रारंभिक चरणों पर विचार करना अनावश्यक है, सिवाय इसके कि 26 अगस्त 1992 को विशेष न्यायालय द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

अपीलकर्ता द्वारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित) के पक्ष में चार चेक निष्पादित किए गए थे, इससे इनकार नहीं किया गया है और न ही यह विवाद था कि अपीलकर्ता के खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस हो गए थे। अदाकर्ता, अर्थात्। आंध्रा बैंक. अपीलकर्ता द्वारा चार चेकों के स्वीकृत निष्पादन के कारण, बैंक अपने मामले के समर्थन में तीन अनुमानों पर भरोसा करने का हकदार था और वास्तव में, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118, 138 और 139 के तहत । धारा 118 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि जब तक कि विपरीत

साबित न हो जाए, यह माना जाएगा कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत विचार के लिए बनाया गया था या तैयार किया गया था, और यह कि प्रत्येक ऐसा लिखत जब इसे स्वीकार कर लिया गया है, पृष्ठांकित किया गया है, बातचीत की गई है या हस्तांतरित किया गया है, तो इसे स्वीकार कर लिया गया है, पृष्ठांकित किया गया है।, बातचीत की गई या विचारार्थ स्थानांतरित किया गया। धारा 138 के तहत उत्पन्न होने वाली धारणा अधिक विशेष रूप से प्रदान करती है कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी ऋण या अन्य देनदारी के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए किसी भी राशि के भुगतान के लिए किसी खाते पर आहरित कोई भी चेक अदाकर्ता बैंक द्वारा बिना भुगतान के वापस कर दिया जाता है। या तो क्योंकि उस खाते में जमा धनराशि चेक का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है, ऐसे व्यक्तियों को अपराध माना जाएगा और उन्हें एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो राशि की दोगुनी राशि तक बढ़ सकती है। चेक, या दोनों के साथ। धारा 138 के तहत अनुमान की प्रकृति प्रस्तुतीकरण, नोटिस देने और चेक जारीकर्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद भुगतान न करने से संबंधित निर्दिष्ट तीन शर्तों के अधीन है। इस मामले में तीनों शर्तों से इनकार नहीं किया गया है. अपीलकर्ता की यह दलील कि चेक 'पूरे या आंशिक रूप से किसी ऋण या अन्य देनदारी के निर्वहन' के लिए नहीं

निकाले गए थे, का उत्तर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत बैंक के पास उपलब्ध तीसरे अनुमान द्वारा दिया गया है। यह धारा प्रदान करती है कि "यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, कि चेक के धारक को किसी भी ऋण या अन्य देनदारी के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है।" ". इन अनुमानों का प्रभाव अपीलकर्ता पर यह साबित करने का साक्ष्यात्मक बोझ डालना है कि चेक किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए बैंक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था क्योंकि धारा 138 और 139 दोनों के लिए आवश्यक है कि न्यायालय चेक जारीकर्ता के दायित्व को " मान ले " । उन राशियों के लिए चेक, जिनके लिए चेक काटे गए हैं, जैसा कि मद्रास राज्य बनाम ए. वैद्यनाथ अय्यर में उल्लेख किया गया है एआईआर 1958 एससी 61 के अनुसार, न्यायालय के लिए प्रत्येक मामले में इस अनुमान को उठाना अनिवार्य है जहां अनुमान को बढ़ाने का तथ्यात्मक आधार स्थापित किया गया है। "यह आपराधिक मामलों में सबूत के बोझ के रूप में सामान्य नियम के अपवाद का परिचय देता है और आरोपी पर जिम्मेदारी डाल देता है" (वही)। इस तरह की धारणा कानून की एक धारणा है, जो तथ्य की धारणा से अलग है जो उन प्रावधानों का वर्णन करती है जिनके द्वारा अदालत मामलों की एक निश्चित स्थिति को "धारणा" कर

सकती है। अनुमान साक्ष्य के नियम हैं और निर्दोषता की धारणा के साथ संघर्ष नहीं करते हैं, क्योंकि उत्तरार्द्ध का मतलब यह है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए बाध्य है। अभियोजन पर दायित्व का निर्वहन कानून या तथ्य की धारणाओं की मदद से किया जा सकता है जब तक कि अभियुक्त अनुमानित तथ्य की गैर-मौजूदगी की उचित संभावना दिखाने वाले सबूत पेश नहीं करता है।

> दूसरे शब्दों में, बशर्ते कि कानून की धारणा का आधार बनाने के लिए आवश्यक तथ्य मौजूद हों, तो न्यायालय के पास वैधानिक निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई विवेक नहीं बचता है, लेकिन यह उस व्यक्ति को इसका खंडन करने से नहीं रोकता है जिसके खिलाफ धारणा बनाई गई है और इसके विपरीत साबित करना. किसी तथ्य को तब सिद्ध माना जाता है जब, "उसके समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय या तो उसके अस्तित्व पर विश्वास करता है, या उसके अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि एक विवेकशील व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, अनुमान पर कार्य करना चाहिए।" कि यह अस्तित्व में है"। इसलिए, खंडन को निर्णायक रूप से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बचाव के समर्थन में न्यायालय

के समक्ष ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि न्यायालय को या तो बचाव के अस्तित्व पर विश्वास करना चाहिए या इसके अस्तित्व को उचित रूप से संभावित मानना चाहिए तर्कसंगतता का मानक यह है कि 'विवेकशील आदमी' का. आवश्यक खंडन साक्ष्य की मात्रा के संबंध में न्यायिक बयान अलग-अलग हैं। कुंदन लाल रल्लाराम बनाम कस्टोडियन, इवेक्यू प्रॉपर्टी, बॉम्बे एआईआर 1961 एससी 1316 में, इस न्यायालय ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 के तहत कानून की धारणा को, कुछ परिस्थितियों में, धारा 114 के तहत उठाए गए तथ्य की धारणा से खारिज किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम. निर्णय उस मामले के तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए। धन्वंतराय बलवंतराय देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1964 एससी 575 में संविधान पीठ के बाद के फैसले में अधिक आधिकारिक दृष्टिकोण रखा गया है, जहां इस न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम वैद्यनाथ अय्यर (सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांत को दोहराया था।) और स्पष्ट किया कि दो प्रकार की धारणाओं के बीच अंतर न केवल न्यायालय के आदेश में है, बल्कि दोनों का खंडन करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति में भी है। विवेकाधीन

अनुमान के मामले में यदि अनुमान लगाया जाता है तो उसे स्पष्टीकरण द्वारा खंडित किया जा सकता है जो "उचित रूप से सत्य हो सकता है और जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप है"। दूसरी ओर एक अनिवार्य अनुमान के मामले में "ऐसे मामले में आरोपी व्यक्ति पर पड़ने वाला बोझ उतना हल्का नहीं होगा जितना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत एक अनुमान लगाया जाता है और उसे ऐसा नहीं माना जा सकता है केवल इस तथ्य के आधार पर बरी कर दिया गया कि अभियुक्त द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण उचित और संभावित है। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि स्पष्टीकरण सत्य है। इस प्रावधान में आने वाले शब्द 'जब तक कि विपरीत साबित न हो' यह स्पष्ट करते हैं कि उपधारणा का खंडन 'प्रमाण' द्वारा किया जाना चाहिए, न कि कोरे स्पष्टीकरण से, जो कि केवल प्रशंसनीय है। किसी तथ्य को तब साबित कहा जाता है जब उसका अस्तित्व सीधे तौर पर स्थापित हो जाता है या जब उसके सामने मौजूद सामग्री के आधार पर न्यायालय को उसका अस्तित्व इतना संभावित लगता है कि एक उचित व्यक्ति इस धारणा पर कार्य करेगा कि यह मौजूद है। इसलिए, जब तक स्पष्टीकरण

सबूत द्वारा समर्थित नहीं है, प्रावधान द्वारा बनाई गई धारणा का खंडन नहीं किया जा सकता है..."

[वीडी झिंगन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1966 एससी 1762 भी देखें; शैलेन्द्रनाथ बोस बनाम बिहार राज्य एआईआर 1968 एससी 1292 और राम कृष्ण बेदु राणे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 (1) एससीसी 366।] इसलिए हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या हमारे सामने मामले में, अपीलकर्ता ने अपने बचाव का समर्थन किया था उसके खिलाफ लगाए गए अनुमान का खंडन करने के लिए पर्याप्त सबूत। मुकदमे में बैंक के मामले के समर्थन में तीन गवाहों से पूछताछ की गई। पहले बैंक के समूह सुरक्षा सलाहकार श्री डेरेक रीड (पीडब्लू 1) थे। श्री रीड ने गवाही दी कि वह बंबई में हुई धोखाधड़ी की जांच करने के लिए बैंक से निर्देश लेकर भारत आए थे, जिसमें बैंक सहित कई बैंक शामिल थे। जांच के दौरान उन्हें चार चेक एक्सटेंशन मिले। बैंक के एक अधिकारी के डेस्क से बी, सी, डी और ई जिसे धोखाधड़ी में शामिल होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है।

बैंक के दूसरे गवाह श्री एस. थे।

ज्ञानविनायगम (पीडब्लू2)। वह आंध्रा बैंक में प्रबंधक, परिचालन थे। उन्होंने बताया कि अपीलकर्ता के खाते में अपर्याप्त धनराशि के आधार पर चार चेक बाउंस हो गए थे। तीसरे गवाह श्री ब्रतींद्र नाथ बनर्जी (पीडब्लू 3)

धोखाधड़ी की जांच के लिए बैंक द्वारा गठित इंडिया टास्क फोर्स के प्रभारी बैंक के निदेशक थे। वह प्राथमिक साक्ष्य था जिस पर बैंक ने भरोसा किया। मोटे तौर पर, श्री बनर्जी ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा धोखाधड़ी के दो मुख्य क्षेत्र थे। उनके अनुसार अपीलकर्ता द्वारा की गई पहली धोखाधड़ी अपीलकर्ता के कहने पर या उसके माध्यम से बैंक द्वारा भुगतान की गई बड़ी रकम से संबंधित थी, जिसके लिए बैंक कोई सुरक्षा या वैध बैंक रसीद प्राप्त करने में विफल रहा था। दूसरी धोखाधड़ी अपीलकर्ता के कहने पर प्रतिभूतियों की वास्तविक खरीद और बिक्री और अपीलकर्ता द्वारा बैंक को प्रतिभूतियों की अनुबंध दर और वितरण दर के बीच अंतर का भुगतान करने में विफलता से संबंधित थी। उन्होंने बैंक के खाते की किताबों और बैंक के व्यवसाय के सामान्य क्रम में बनाए गए अन्य रिकॉर्ड के आधार पर अपीलकर्ता और बैंक के बीच लेनदेन से संबंधित बयानों का सत्यापन किया। सभी बयान (उदा. ओ, पीक्यू और टी) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए और अपीलकर्ता द्वारा बिना किसी आपत्ति के प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किए गए। पहला विवरण 8.11.1991 और 18.12.1991 के बीच की अवधि से संबंधित था और इसमें अनुबंध दरों, वितरण दरों, अंतर की दरों और उल्लिखित प्रतिभूतियों के अंतर की मात्रा को दर्शाया गया था। डील पर्चियों, लागत मेमो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और चार डील पर्चियों के संबंध में क्लियरिंग शीट में प्रविष्टि के साथ विवरण को एक्सट के रूप में चिह्नित किया गया था। 'ओ'. विस्तार से बाहर. 'ओ', चार डील

पर्चियों में शामिल दरों का अंतर अपीलकर्ता द्वारा 15 करोड़ रुपये का चेक देकर तय किया गया था। इस खाते पर शेष राशि 45,77,40,250/- रुपये थी। श्री बनर्जी द्वारा तैयार और प्रमाणित किया गया दूसरा वक्तव्य एक्सटेंशन था। 28.12.1991 से 17.2.1992 के बीच लेनदेन के संबंध में 'पी' तैयार किया गया। बयान को 18 डील पर्चियों द्वारा समर्थित किया गया था। इस खाते पर अपीलकर्ता की देनदारी 56,50,50,000/- रुपये होने का दावा किया गया था। विस्तार. 'पी' को बाद में एक्सटेंशन द्वारा सही किया गया। 'टी' जिसने एक्सटेंशन द्वारा कवर की गई अवधि के लिए अपीलकर्ता की देनदारी का आंकड़ा दिया। 'पी' रु. 39,50,50,000/-। तीसरे कथन को एक्सटेंशन के रूप में चिह्नित किया गया था। 'क्यू'। इसमें 21.2.1992 से 27.3.1992 तक की अवधि के दावे का विवरण दिया गया। इस अवधि के लिए अपीलकर्ता की देनदारी 30,97,34,135/- रुपये होने का दावा किया गया था। विस्तार. 'क्यू' को पांच डील पर्चियों का समर्थन प्राप्त था।

सभी सौदा पर्चियाँ जो मुद्रित प्रपत्र थीं और क्रमबद्ध रूप से क्रमांकित थीं, अनुबंध दर और वितरण दरें दर्शाती थीं.. वे बैंक के डीलरों द्वारा तैयार की गई थीं। श्री बनर्जी ने यह भी कहा कि जिस कॉलम में ब्रोकर के नाम की आवश्यकता थी, उसमें संक्षिप्त नाम 'डीआईआर' का उपयोग अपीलकर्ता को संदर्भित करता था। गवाह ने यह भी दिखाया कि कुछ लेनदेन के संबंध में जहां अनुबंध दर वितरण दर से कम थी, अपीलकर्ता को बैंक द्वारा भुगतान किया गया था। अपीलकर्ता के मामले से निपटने में अर्थात् चेक

उन इच्छित सौदों के लिए दिए गए थे जो कभी हुए ही नहीं थे, श्री बनर्जी ने कहा कि उन्होंने सभी सौदे पर्चियों को देखा है जो उनके साथ अदालत में लाए गए थे और कोई सबूत नहीं था अपीलकर्ता और बैंक के बीच किसी भी सौदे के रद्द होने पर। अपनी जांच के दौरान, श्री बनर्जी ने बैंक द्वारा अपीलकर्ता को 1240 करोड़ रुपये के भुगतान और बैंक रसीदें/प्रतिभूतियां प्रस्तुत न करने के कारण बैंक को हुए नुकसान के साक्ष्य भी दिए।

बैंक की ओर से दो और गवाह पेश किये गये। एक ने बैंक में अपीलकर्ता के खाते को साबित किया और दूसरे ने संबंधित अवधि के लिए आंध्रा बैंक में अपीलकर्ता के खाते को साबित किया।

जहां तक अपीलकर्ता के बचाव का सवाल है, उसने अपने मामले का समर्थन करने के लिए गवाह बॉक्स में प्रवेश नहीं किया कि विशेष रूप से चार चेक किसी व्यवस्था के संबंध में या किसी लेनदेन के संबंध में दिए गए थे जो अमल में नहीं आए। दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए लोगों के अलावा अपीलकर्ता द्वारा बुलाए गए चार गवाह थे, श्री रमेश लक्ष्मण कामत (डीडब्ल्यू 1) श्री एसआरए राव (डीडब्ल्यू 2), श्री जीडी भल्ला (डीडब्ल्यू 3) और श्री जी. सीकेसी तालुकदार ( डीडब्ल्यू.

4). विशेष न्यायालय ने पाया कि डीडब्ल्यू 1 के साक्ष्य श्रेय के योग्य नहीं थे और "लगभग सभी बिंदु जिनमें अप्रासंगिक बिंदु और बिंदु शामिल थे जिन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता था, (उन्होंने) टाल-मटोल

किया..... (और)..... सत्य को तब तक नकारने की कोशिश की गई जब तक कि सत्य को नकारा नहीं जा सकता था।" डीडब्ल्यू 1 उस समय भारतीय स्टेट बैंक (जिसे एसबीआई कहा जाता है) के उप महाप्रबंधक थे। उन्होंने यह तर्क देने की कोशिश की थी कि चार बयानों में उल्लिखित कई लेनदेन। पूर्व. ओ, पी और क्यू बैंक और एसबीआई के बीच तैयार लेनदेन थे, और प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद को प्रतिबिंबित नहीं करते थे। यह एक ऐसा मामला था जिसे वह पहले से ही रिकॉर्ड पर मौजूद या सीबीआई की हिरासत से पेश किए गए दस्तावेजों के संदर्भ में साबित करने में असमर्थ थे। गवाह द्वारा स्वयं प्रस्तुत किये गये दस्तावेज विशेष न्यायालय द्वारा संदिग्ध पाये गये। बचाव पक्ष के दूसरे गवाह, श्री एसआरए राव ने यह भी स्थापित करने की कोशिश की कि Ex.O में एक लेनदेन अस्तित्वहीन या एक डमी लेनदेन था। तीसरे बचाव गवाह, श्रीमान. आंध्रा बैंक के शाखा प्रबंधक जीडी भल्ला ने साबित किया कि अपीलकर्ता ने बैंक को कई करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

चौथे गवाह, भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कर्मचारी अधिकारी, जीके तालुकदार ने यह दिखाने के प्रयास में कई प्रतिभूतियों की अनुबंध दरों को निर्धारित करने वाली एक सूची तैयार की कि बैंक द्वारा दावा की गई अनुबंध दरें सही नहीं थीं। यह नहीं बताया गया कि सूची बैंक पर लागू होती है या अन्य दरों के लिए अनुबंध नहीं किया जा सकता है।

अपीलकर्ता के गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य का खामियाजा अपीलकर्ता और बैंक के बीच लेनदेन की प्रकृति से था। हालाँकि, बचाव पक्ष के किसी भी गवाह ने अपीलकर्ता के एकमात्र बचाव के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया, अर्थात् कि प्रश्न में चार चेक इच्छित लेनदेन के लिए दिए गए थे जो नहीं हुए। किसी ने यह नहीं बताया कि अपीलकर्ता ने बैंक को विशेष चेक क्यों निष्पादित और वितरित किए थे या अपीलकर्ता ने बैंक को अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए चार चेक क्यों नहीं दिए थे। न ही बचाव पक्ष के किसी गवाह ने यह दावा किया कि चेक में किसी तैयार अग्रिम लेनदेन का लेखा-जोखा दिया गया था। वास्तव में, डीडब्ल्यू 1 ने जिरह में स्वीकार किया कि खरीदने वाली पार्टी के लिए पहले से चेक सौंपना प्रथा नहीं है। अकेले अपीलकर्ता ही बता सकता था कि उसने चार चेक क्यों स्वीकार किए, उन्हें बैंक को सौंप दिया और उन्हें वापस करने के लिए कभी नहीं कहा। उन्होंने ऐसा करना नहीं चुना.

जैसा कि विशेष न्यायालय ने कहा:

> "इस प्रकार अभियुक्त के अनुसार, चेक Ex. B और C 23 दिसंबर 1991 को वितरित किए गए थे। यह स्पष्ट रूप से 2 करोड़ और 1.08 करोड़ इकाइयों की इच्छित खरीद के लिए था। उसके अनुसार चेक Ex. D 17 फरवरी 1992 को दिया गया था। यह कथित तौर पर 1,22,50,000

इकाइयों की इच्छित खरीद के लिए दिया गया था। पूर्व ई को कथित तौर पर 27 मार्च 1992 को कैन स्टार की 7 करोड़ इकाइयों और कैन प्रीमियम की 10 करोड़ इकाइयों की खरीद के लिए दिया गया था। लिखित में जो कहा गया है उसके अलावा बयान में कहा गया है कि इस मामले के समर्थन में कोई साक्ष्य या सबूत नहीं है।"

एसएस के तहत अनुमानों को अस्वीकार करने का भार अपीलकर्ता पर था। 138 और 139 एक बोझ है जिसे वह उतारने में बिल्कुल भी असफल रहा। अपीलकर्ता के लिखित बयान में कहा गया कथन पर्याप्त नहीं था। संयोग से, लिखित बयान में बचाव कि चार चेक इच्छित लेनदेन के लिए दिए गए थे,

अपीलकर्ता द्वारा धारा 138 के तहत नोटिस का जवाब नहीं था । तब उन्होंने कहा था कि ये चेक बैंक के पुनर्गठन (एक्स.एच.) में सहायता के लिए दिए गए थे। अपीलकर्ता के लिए कम से कम स्वीकार्य साक्ष्य के आधार पर यह दिखाना आवश्यक था कि लिखित बयान में उसका स्पष्टीकरण इतना संभावित था कि एक विवेकशील व्यक्ति को इसे स्वीकार करना चाहिए या यह स्थापित करना चाहिए कि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का प्रभाव, इसकी समग्रता ने कल्पित तथ्य के अस्तित्व को असंभव बना दिया। (देखें त्रिलोक चंद जैन बनाम दिल्ली राज्य 1975 (4)

एससीसी 761)। अपीलकर्ता ने कुछ भी नहीं किया है। ऐसे किसी भी सबूत के अभाव में धारा 138 और 139 के तहत अनुमान प्रभावी होना चाहिए। हम यहां यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि बी. बनर्जी (पीडब्लू 3) द्वारा उल्लिखित धोखाधड़ी के पहले क्षेत्र के संबंध में अपीलकर्ता से धन की वसूली के लिए बैंक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में, इस न्यायालय ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम कस्टोडियन (2000 (6) ) में एससीसी 427) ने विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए पाया कि अपीलकर्ता बैंक को 280.00 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, जो कि संबंधित चार चेकों द्वारा कवर की गई राशि से कई गुना अधिक है। विशेष न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता का यह तर्क कि वास्तव में धारा 138 के तहत कोई अपराध नहीं किया गया था, क्योंकि वह चाहकर भी नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं कर सकता था, सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता की दलील इस तथ्य पर आधारित थी कि उसे संरक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 3 के तहत सूचित किया गया था और परिणामस्वरूप उसकी सभी संपत्तियाँ कुर्क कर ली गई थीं। लेकिन, जैसा कि विद्वान विशेष न्यायालय ने देखा, विशेष न्यायालय के समक्ष कई पक्षों द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अनुमति मांगने के लिए कई आवेदन थे। कुछ मामलों में न्यायालय ने उन्हें अनुमति दे दी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो अपीलकर्ता को अपने दायित्वों को पूरा करने या चेक एक्स के तहत अपने ऋणों का भुगतान

करने की अनुमति के लिए विशेष न्यायालय में आवेदन करने से रोकता हो। बी, सी, डी और ई। अपीलकर्ता द्वारा अस्वीकृत चेक के लिए कोई भुगतान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। अपीलकर्ता ने भुगतान नहीं किया होगा भले ही वह कर सकता हो। यह न केवल पत्राचार और अपीलकर्ता के आचरण से स्पष्ट है, बल्कि दायित्व से पूरी तरह इनकार करने के उसके बचाव से भी स्पष्ट है। इसलिए तर्क पूरी तरह अकादमिक था।

विशेष अदालत ने अपीलकर्ता के बचाव को असंभव पाया और उसके उदाहरण पर पेश किए गए सबूत त्रुटिपूर्ण और अविश्वसनीय थे। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों को सावधानीपूर्वक स्कैन करने और अंततः परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 , 138 और 139 के तहत वैधानिक रूप से प्रदान की गई धारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बाद , अपीलकर्ता को दोषी पाया गया। पहले बताए गए कारणों से, हमारे लिए अपीलकर्ता को उस अपराध के लिए दोषी ठहराने में विशेष न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से अलग निर्णय लेने और अलग होने का कोई आधार नहीं है, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। इसलिए हम विशेष न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हैं और 10,000/- रुपये की लागत के साथ अपील को खारिज करते हैं।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सत्येन्द्र सिंह चौहान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

सत्येन्द्र सिंह चौहान

(आर.जे.एस.)